

बजट अनुमान 2009-2010

बजट अनुमान 2009-10 में वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1,19,885 करोड़ रुपए की निवल बढ़ोतरी दिखाई गयी है। आयोजना-भिन्न व्यय में 77,693 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आयोजना व्यय के अन्तर्गत 42,192 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। आयोजना-भिन्न तथा आयोजना व्यय अनुमानों में मुख्य मदों की घट-बढ़ को नीचे सारणी में दिया गया है:

	(करोड़ रुपए)		
	संशोधित 2008-09	बजट 2009-10	घट-बढ़ कमी(-)/ वृद्धि(+)
आयोजना-भिन्न			
1. ब्याज संदाय और ऋण शोधन	192694	225511	(+) 32817
2. रक्षा व्यय	114600	141703	(+) 27103
3. राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान	37255	47519	(+) 10264
4. खाद्य सब्सिडी	43627	52490	(+) 8863
5. आयोजना भिन्न पूंजी परिव्यय (रक्षा छोड़कर)	13694	21056	(+) 7362
6. पुलिस	20711	25390	(+) 4679
7. सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न अनुदान और ऋण	799	3485	(+) 2686
8. पेंशन	32690	34980	(-) 2290
9. शिक्षा	5925	7779	(-) 1854
10. डाक घाटा	3825	5395	(+) 1570
11. कृषि और संबद्ध सेवाएं	5891	2438	(-) 3453
12. उर्वरक सब्सिडी	75849	49980	(-) 25869
13. अन्य (आयोजना-भिन्न) व्यय	70436	77963	(-) 7527
जोड़ (आयोजना-भिन्न) व्यय	617996	695689	(+) 77693
आयोजना			
1. केन्द्रीय आयोजना	204129	239840	(+) 35711
2. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	78828	85309	(-) 6481
जोड़ (आयोजना) व्यय	282957	325149	(+) 42192
जोड़ व्यय (आयोजना+आयोजना भिन्न)	900953	1020838	(+) 119885

आयोजना-भिन्न

- बाजार ऋणों पर ब्याज की अधिक अदायगी और तेल विपणन कम्पनियों और उर्वर कम्पनियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज के प्रावधान के लिए।
- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी और रक्षा बलों के आधुनिकीकरण की वर्धित आवश्यकता के कारण।
- यह वृद्धि मुख्यतया राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत दिए जाने वाले अधिक अनुदानों तथा केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने के कारण राज्यों को राजस्व हानि के लिए की जाने वाली प्रतिपूर्ति के कारण हुई है।
- यह वृद्धि मुख्यतः बीपीएल परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, उच्च अधिप्राप्ति के लिए परिवहन लागत में हुई वृद्धि इत्यादि के कारण हुई है।
- यह वृद्धि मुख्यतः अन्य बातों के अलावा भारत के कोटे में हुई वृद्धि से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान हेतु अधिक आवंटन करने, पुलिस में

संबंधित अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के कारण हुई है।

- यह वृद्धि मुख्यतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण हुई है।
- यह वृद्धि मुख्यतः भारतीय टेलीफोन उद्योग (आईटीआई) लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान करने के कारण हुई है।
- यह वृद्धि मुख्यतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा पेंशनभोगियों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण हुई है।
- यह वृद्धि मुख्यतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण हुई है।
- यह वृद्धि मुख्यतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण हुई है।
- यह वृद्धि मुख्यतः सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए नाबार्ड को दिए जाने वाले अनुदानों के लिए संशोधित अनुमान 2008-09 में किए गए प्रावधान के कारण।
- कमी मुख्यतः स्वदेशी और आयातित उर्वरकों के साथ-साथ विनियंत्रित उर्वरकों की आर्थिक लागत में प्रत्याशित कटौती के कारण कम सब्सिडी का प्रावधान करने के कारण हुई है।

आयोजना

- यह समग्र वृद्धि कृषि अन्य बातों के साथ-साथ और सहकारिता, पशुपालन, डेरी और मछली पालन, उर्वरक, कोयला, औद्योगिक नीति और संवर्धन, डाक सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता मामले, संस्कृति, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण और वन आर्थिक कार्य, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुष, भारी उद्योग, गृह, आवास और शहरी, गरीबी उन्मूलन, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, उच्चतर शिक्षा, सूचना और प्रसारण, श्रम और रोजगार विधि और न्याय, अल्पसंख्यक मामले, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, योजना, विद्युत, ग्रामीण विकास, भू-संसाधन, पेय जलापूर्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राज मार्ग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, अंतरिक्ष, वस्त्रोद्योग, जनजातीय कार्य, जल संसाधन, महिला और बाल विकास, युवा मामले और खेल तथा रेलवे में वृद्धि के निवल प्रभाव के कारण है और दूर संचार तथा शहरी विकास में कमी के कारण है।
- यह समग्र वृद्धि सामान्य केन्द्रीय सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, विशेष केन्द्रीय सहायता, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, जेएनएनयूआरएम, त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम, ब्रिम्स्टोवा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वन क्षेत्र की बहाली और पुनर्सृजन के त्वरित कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, बैंक रहित खंडों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए अवसंरचना सहायता हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, अनुसूची-V क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और मुंबई मेट्रो रेल परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वृद्धि के निवल प्रभाव के कारण और कमी 2005-06 के दौरान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए परिसंपत्तियों के दीर्घावधिक पुनर्निर्माण सहायता तथा सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के कारण है।